



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 1985/चैत्र 8, 1907

No. 160]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 1985/CHAITRA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1985

का. आ. 276(अ)/18कक/उ. वि. वि. अ./85 :—
केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और
नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश
सं. का. आ. 319 (अ)/18कक/उ. वि. वि. अ./76
तारीख 27 अप्रैल, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात
उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स प्लाईवोर्ड इंडस्ट्रीज लिमि-
टेड, पाम्पोर, जम्मू कश्मीर नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम
का प्रबन्ध 26 अप्रैल, 1981 तक की, जिसमें यह तारीख भी
सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए
जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्राधिकृत किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोक-
हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच वर्ष
की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रभावी बना रहे 31 मार्च,
1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है,

और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए समय-समय पर
निर्देश जारी किए थे (देखिए भारत सरकार के उद्योग
मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ.
318(अ)/18कक/उ. वि. वि. अ./81, तारीख 25 अप्रैल,
1981, सं. का. आ. 287 (अ)/18कक/उ. वि. वि. अ./
82, तारीख 26 अप्रैल, 1982, सं. का. आ. 763 (अ)/
18कक/उ. वि. वि. अ./82, तारीख 25 अक्टूबर, 1982,
सं. का. आ. 233 (अ)/18कक/उ. वि. वि. अ./83,
तारीख 28 मार्च, 1983, सं. का. आ. 695 (अ)/18कक/
उ. वि. वि. अ./83, तारीख 29 सितंबर, 1983, सं.
का. आ. 227 (अ)/18कक/उ. वि. वि. अ./84, तारीख
30 मार्च, 1984, सं. का. आ. 473 (अ)/18कक/उ. वि.
वि. अ./84, तारीख 28 जून, 1984, सं. का. आ. 748
(अ)/18कक/उ. वि. वि. अ./84, तारीख 28 सितंबर,
1984, और सं. का. आ. 973 (अ)/18कक/उ. वि. वि.
अ./84, तारीख 29 दिसंबर, 1984) ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह
समीचीन है कि उक्त आदेश 30 जून, 1985 तक की, जिसमें
यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना
रहे,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उप-धारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18कक की उप-धारा (2) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 30 जून, 1985 तक को, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित हो, और अर्थात् के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 2(6)/81-सी. यू. एस.]

ए. पी. सरवान, मंत्रालय सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th March, 1985

S.O. 276(E)|18AA|IDRA|85.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 319(E)|18AA|IDRA|76, dated the 27th April, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Jammu and Kashmir Industries Limited to take over the management of the whole of the Industrial undertaking known as Messrs Plyboard Industries Limited, Pampore, Jammu and Kashmir, for a period of five years, that is, upto and inclusive of the 26th April, 1981.

And, whereas, the Central Government being of the opinion that it is expedient in public interest

that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1985 (vide orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 318(E)|18AA|IDRA|81, dated the 25th April, 1981, S.O. 287(E)|18AA|IDRA|82, dated the 26th April, 1982, S.O. 763(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th October, 1982, S.O. 233(E)|18AA|IDRA|83, dated the 28th March, 1983, S.O. 695(E)|18AA|IDRA|83, dated the 29th September, 1983, S.O. 227(E)|18AA|IDRA|84, dated the 30th March, 1984, S.O. 473 (E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984, S.O. 748(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th September, 1984 and S.O. 973 (E)|18AA|IDRA|84, dated the 29th December, 1984);

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1985.

[File No. 2(6)|81-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.